

राज्य सरकार डजिटल भूमिअभिलेखों की घर-घर शुरू करेगी डलिवरी

चर्चा में क्यों?

11 मार्च, 2022 को बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने विधानसभा में बताया कि बिहार सरकार जल्द ही राज्य में खतियान और मानचित्र सहित भूमि के डजिटल दस्तावेजों को घर-घर पहुंचाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जहाँ लोगों को डजिटल भूमि दस्तावेजों की डोरस्टेप डलिवरी की सुविधा मिलेगी।
- राज्य के गाँवों, कस्बों और शहरों का राजस्व मानचित्र अब ऑनलाइन मँगाया जा सकता है। डाक विभाग द्वारा डजिटल राजस्व/भूमि अभिलेखों के वितरण के लिये स्पीड पोस्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों को खतियान (कब्जा निर्धारित करने के लिये भूमि की पहचान करने का एक दस्तावेज) सहित ज़मीन से जुड़े किसी भी दस्तावेज के लिये सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
- राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने वाणज्याके एवं आवासीय, दोनों क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिये अप्रैल में एक गहन अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान निर्वाचन क्षेत्र औराई (मुज़फ़्फ़रपुर) से शुरू होगा और इसे राज्य के अन्य हिस्सों में चलाया जाएगा।